



संख्या-1463 04xxv111-3-2023-E file no. 40141

प्रेषक,

डॉं० आर० राजेश कुमार, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, चिकित्सा खारथ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—3 देहरादून : दिनांक / ७ अगस्त, 2023 विषय—ECRP-II के अन्तर्गत जनपद चम्पावत Emergeney Covid Response Package-II (ECRP-II) के अन्तर्गत (50 Bedded) Critical Care Block की स्थाना के संबंध में महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7प/1/निर्माण/37/2021/भाग-9578, दिनांक 27.3.2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिस्के द्वारा ECRP-II के अन्तर्गत जनपद जनपद चम्पावत में Emergency Covid response paclage -II (ECRP-II) के अन्तर्गत 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना के कार्यों के आगणन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (ब्रिडकुल) के माध्यम से तैयार कराकर शासन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया हैं।

2— अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के नियोजन विभाग की टीoएoसीo द्वारा परीक्षणोपरान्त विभागीय सिगति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्माण कार्यों पर अनुमोदन प्रदान किया है। जिनका विवरण निम्नलिखित है

निर्माण कार्य का नाम	कार्यदायी संस्थ	प्रस्तावित कार्य के नियोजन विभाग की टी रागी. के पशेक्षणोपरान्त आगणन की आगणन की लागत					
		लागत		सिविल	य कार्य	अधिप्राप्ति कार्य	कुल
ECRP -II के अन्तर्गत जनपद चम्पायत में 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना।	चि <u>ड</u> कुल	रू0 लाख	2023.95	रु0 लाख		550450.86 त्याख	₹50 2022.90
कुल योग		• 071					জ0 2022.90



/146304/2023

अतः उत्तत तालिकानुसार एन०एच०एम० के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में भारत सरकार से ECRP-II एवं PM-ABHIM के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि जो कि संगत राज्यांश (10%) के साथ सुसंगत लेखाशीर्षक से वित्तीय स्वीकृति के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन०एच०एम० को उपलब्ध करायी गयी है, से तालिकानुसार धनराशि रू० 2022.90 लाख (रूपये बीस करोड़ बाईस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापक्ष वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31.3.2023 के प्रस्तर—14 (3) के प्राविधानुसार प्रथम चरण में 40 प्रतिशन धनराशि रू० 809.16 लाख (रू० आठ करोड नौ लाख सोलह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्ता / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

- ा. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।
- II. कार्यों को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी प्रत्येक कार्य हेतु मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- IV. प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उच्चाधिक रियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थलों का भली—भ ति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- v. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के डिजाइन एवं ड्राइंग को भारत सरकार से अनुमोदित प्रख्यात संस्था से विधिक्षित (VET) कराया जायेगा।
- VI. प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यों की स्ट्रक्चरल ड्रांइग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आगणन में उन्हीं मदों का समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं।
- VII. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथा बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- vIII. निर्माण कार्यो में स्ट्रक्चर एवं Reinforcement Steel हेतु शत-प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।
 - IX. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय—समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।
 - x. निर्माण हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विशेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।

- XI. इलैक्ट्रीक आईटम्स जैसे—Switches, Wires, MCB, MCCB, AC vkfn Pluming Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes Toilet Items, Wood Items आदि क्य Market Survey/डी०एस०आर० दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग के साध समन्वय स्थापित कर ब्राण्ड नेम निर्धारित कर लिया जाय।
- XII. बिल्डिंग से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित किया जाय।
- XIII. कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशास्कीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने हेतु नियोजन विभाग को अवश्य सूचित कराया जाय।
- xiv. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भद स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से शासन को अटगत करायेंगे।
- xv. विभागाध्यक्ष / सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रवचरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
- xvi. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहल ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- XVII. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाय।
- xvIII. सुसंगत गद से एन०एच०एम० को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।
 - XIX. मिशन निदेशक. राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय-समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - xx. उद्भत निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 02 जून, 2023 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या—954 दिनांक 15 जून, 2023 में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xxi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—475/ XXVII(7)/2008. दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपन्न पर नियमानुसार एम0ओ0यू० अवश्य हरताक्षरित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यों को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हरतगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थित में पुनरीक्षण या अन्य किसी नये मद को जोड़ने की अवश्यकता होती हो

z146<u>304</u>72023

तो पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दशा में आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

xxII. अग्रिम किस्ता को व्यय करने की अनुमति उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही प्रदान की जायेगी।

XXIII. यह आदेश वित्त विभाग के अ०१११० संख्या--144565 / 2023,दिनांक 7-8-2023 अगस्त, 2023 में प्रदत्त सहमति के कम में निगत किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by R. Rajesh Kumar Date: 14-08-2023 12:40:44

(डॉं० आर० राजेश कुमार) सचिव।

संख्या— १५ ६३ ७५/XXVIII-3-2023-E file no. 4014), राद्दिनांक प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवार्हः हेतु प्रेषित :—

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालंखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
- 2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, चम्पचत्।
- 4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 5. <u>मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत</u>ः
- मुख्य कोष विकारी / कोषाधिकारी, जम्यावत ।.
- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा मेशन निवेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड वेहराद्न।
- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
- 10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड संचिवालय, उत्तर खण्ड, देहर दून।
- 11. गार्ड फईल।

आज्ञा से

जिस्तीविक्दर कौर) अनु संचिव।